आर्थिक स्थिति के आधार पर जनगणना

53. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अगली जनगणना के दौरान भारतीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके उनके रहन-सहन के स्तर के संबंध में सूचना एकत्र करने हेतु कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो आर्थिक स्थिति के आधार पर बनाई गई श्रेणियों की कुल संख्या कितनी है तथा परत्येक श्रेणी के अंतर्गत नागरिकों की कितनी-कितनी वार्षिक आय निर्धारित की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जनसंख्या की गणना में भारतीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हुए उनकी जीवन शैली के बारे में सही और विश्वसनीय जानकारी एकत्रित करना संभव नहीं है। अतः देश की जनगणना में इस प्रकार की जानकारी एकत्र करने की कोई परिपाटी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

Barbed wire fencing of borders

54. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) when the decisions were taken for barbed wire fencing in each State of the country's borders with Pakistan and Bangladesh, sector-wise;

(b) when this work was started and what was the stipulation of its completion, sector-wise;

(c) the agencies who have been assigned this work;

(d) the reasons for delay in completion of this work;

(e) what is the target date of completion of this work now; and

(f) what is the estimated cost involved?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (f) The latest position with regard to fencing and flood lighting on Indo-Pak and Indo-Bengladesh borders is as under:—

(I) *INDO-PAK BORDER:*

The sector-wise position is as under:—

(a) *Punjab Sector:*

Erection of fencing on 452 Kms and flood lighting on 460 Kms of the border was sanctioned in various phases from 1988-89 and was completed by December, 1993 at a cost of Rs. 141.90 crores. The entire feasible length of border was fenced/flood light. The work was executed by CPWD.

(b) *Rajasthan Sector:*

Fencing/flood lighting on Rajasthan border was sanctioned in various phases from 1989-90 to 1996-97 and upto December, 1997 fencing/flood lighting on 865 Kms of border has been completed at a cost of Rs. 354.48 crores. The fencing/flood lighting on 167.5 Kms of border is under exeuction and will be completed by December, 1999 in two phases at a cost of Rs. 56.24 crores. For the remaining border with shifting sand dunes also, specially designed Single Row Fencing will be erected. The work is being executed by CPWD.

(c) *Jammu Sector:*

Fencing/flood lighting on 180 Kms/ 195.8 Kms of Jammu International Border was sanctioned in March, 1995 at an estimated cost of Rs. 71.76 crores and the work was started by CPWD in July, 1995 but the same had to be suspended due to persisted firing from Pakistan side. The matter regarding restarting the work is under active consideration of the Government.

(d) *Gujrat Sector:*

Fencing/flood lighting of 10 Kms of Gujarat border in the Luni Basin has been sanctioned in December, 1997 at an

estimated cost of Rs. 9.75 crores and is targetted to be completed by December, 1999 along with the work in Rajasthan sector. Also a proposal for fencing/flood lighting of 310 Kms of the border is under consideration of the Government and will be taken up after completion of the work in Rajasthan sector. The work will executed by the CPWD.

(II) *INDO-BANGLADESH BORDER:*

In February, 1986, Govt. of India had approved a proposal for providing 337 Kms of fencing along Indo-Bangladesh border (202 Kms in Assam and 135 Kms in Meghalaya). The proposal was revised in 1992 and fencing of 896 Kms of border (158 Kms in Assam, 231 Kms in Meghalaya and 507 Kms in West Bengal) was sanctioned for completion upto March, 1998. The revised proposal included construction of roads as well as bridges also. The total project cost was Rs. 1012.71 crores and the sector-wise position is as under:—

(a) *Assam Sector:*

The fencing on this sector was sanctioned in various phases from 1989—1995 and Assam PWD has erected fencing on 132 Kms of border. Fencing on 20 Kms of border is under execution in last two stretches near Tripura border.

(b) *Meghalaya:*

The fencing in this sector was sanctioned in different phases from 1991 to 1996 and Border Roads Organsiation has already completed fencing on entire about 200 Kms. border.

(c) *West Bengal:*

In the West Bengal sector, fencing was sanctioned in 1993-94 and nearly 445 Kms of border has been fenced by CPWD. The work on remaining 62 Kms of border is likely to be completed by March, 2001.

The reasons for slow pace of work on Indo-Bangladesh border are due to slow progress of land acquisition in West Bengal, objections from local people in Meghalaya, remoteness and difficult working conditions and disturbed conditions including insurgency in the North Eastern States.

छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण

55. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने हेतु आधिकारिक घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण तत्काल किया जा सके;

(ग) प्रस्तावित राज्य में शामिल किये जाने वाले जिलों के नाम क्या-क्या हैं तथा इस राज्य की राजधानी कहां स्थित होगी; और

(घ) क्या सरकार उक्त छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नवंबर, 1998 से पहले कर देगी, ताकि इस प्रस्तावित राज्य की विधान सभा के चुनाव राज्य की विधान सभा के चुनावों के साथ ही कराये जा सकें?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) नये, राज्य छत्तीसगढ़ का सृजन करना, सरकार द्वारा शासन के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय कार्यसूची का एक भाग है। जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा 25.3.1998 को संसद में दिए गए भाषण में निर्दिष्ट किया गया था, कि प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश, में से बनाया जाएगा। इस संबंध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाने के बारे में कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाये या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाये, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुरः स्थापित नहीं किया जाएगा। नए राज्य का सृजन करने से पहले विधेयक पर संसद द्वारा विचार किये जाने और इसे पारित करने की आवश्यकता है।